समाज के हर वर्ग तक संवाद और संपर्क बनाना जरूरी

भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक को संबोधित करते हुए सीएम डॉ. यादव ने कहा

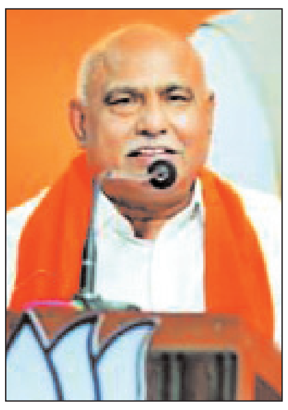

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 17 अप्रैल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में संभाग और जिला प्रभारियों की बैठक को संबोधित किया.

बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग-2026 पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि पार्टी के कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने के लिए कार्यकर्ताओं की मेहनत और एकजुटता अनिवार्य है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार के विकासोन्मुखी योजनाओं को समाज के हर वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंचाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ जुटना है. जब तक हम सब मिलकर पार्टी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, तब तक हमारी योजनाओं में सफलता नहीं मिल सकती. पार्टी की सफलता केवल चुनावी जीत में नहीं, बल्कि समाज में भाजपा की स्थायी पहचान और सेवा की भावना से भी जुड़ी हुई है. हमें समाज के हर वर्ग से संवाद बढ़ाना होगा, उनकी समस्याओं को समझते हुए पार्टी की नीतियों का लाभ समाज तक पहुंचाना होगा. भाजपा का विचार और उसकी नीतियां समाज के हर वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए अधिक प्रभावी बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है. चुनौतियों का सामना करते हुए हमें पार्टी के उद्देश्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यही भाजपा की असली ताकत है और यही पार्टी के भविष्य की सफलता सुनिश्चित करेगा. वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत हैं.

राहुल की भाषा संसदीय गरिमा के अनुकूल नहीं

बाद में मीडिया से चर्चा में प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा कि आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष द्वारा बार-बार व्यवधान उत्पन्न किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा सदन में प्रयुक्त भाषा संसदीय गरिमा के अनुकूल नहीं है. देश के इतिहास में इस प्रकार की असंतुलित एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग पहले नहीं हुआ. सभी को संसदीय भाषा का उपयोग करना चाहिए.

हमारी सरकार और संगठन की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा, ताकि भाजपा की नीतियों और योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके. भाजपा की जीत केवल चुनावी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि समाज में पार्टी की स्थायी पहचान और सेवा की भावना से जुड़ी हुई है. पार्टी की सफलता का आधार सिर्फ चुनावी जीत नहीं है, बल्कि समाज के प्रति हमारी सेवा और भाजपा की स्थायी पहचान भी है. हमें सिर्फ चुनावी सफलता ही नहीं, बल्कि समाज में स्थायित्व और विकास के लिए सक्रिय रूप से काम करना होगा.

एक नजर में

नरवाई जलाने से 50 खेतों में आग, प्राथमिकी दर्ज

सिवनी. जिले के मुंगवानी कला गांव में नरवाई जलाने के कारण आग फैलने से करीब 50 खेत प्रभावित हो गए, जिससे किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. सिवनी विकासखंड के मुंगवानी निवासी पवन यादव अपने खेत में नरवाई जला रहा था. ग्रामीणों द्वारा मना करने के बावजूद उसने आग लगाई, जो तेज हवा के चलते बेकाबू होकर आसपास के खेतों तक फैल गई. पटवारी की प्रारंभिक रिपोर्ट में नितेश ठाकुर के 100 पाइप, रामलाल यादव के 200 पाइप एवं तीन मोटर, नंदकिशोर यादव के 70 स्प्रिंकलर पाइप सहित अन्य किसानों की विद्युत वायरिंग जलने की पुष्टि हुई है.

ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत

मुरैना. मुरैना जिले के कैलारस थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस सूत्रों के अनुसार यह दुर्घटना ग्राम खैरा की तौर में हुआ. महेश शाक्य अपने पुत्र सौरभ की शादी के लिए एक महिला परिजन के साथ बाइक से सामान लेने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में महेश शाक्य की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि बाइक पर सवार महिला आरती गंभीर रूप से घायल हो गई. ग्रामीणों ने घायल को पहले कैलारस अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल मुरैना रेफर किया गया.

मध्यप्रदेश में चिलचिलाती धूप और लू का सितम

20 जिलों में लू की चेतावनी

भोपाल, 17 अप्रैल. मध्य प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है. दोपहर के समय तेज और चिलचिलाती धूप के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. सूर्यास्त के बाद भी गर्म हवाओं से राहत नहीं मिल रही है और रात तक गर्मी का असर बना रहता है.

मौसम विभाग ने प्रदेश के लगभग 20 जिलों में लू (हीट वेव) चलने की गंभीर चेतावनी जारी की है. हालांकि 19-20 अप्रैल के आसपास कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है. इंदौर में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस रहा.

लगातार बढ़ती गर्मी का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है. दिन के समय बाजारों में भीड़ कम हो गई है और लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं. अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है. जिला अस्पताल, एमवाय अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में उल्टी, दस्त, चक्कर और लू से प्रभावित मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है. डॉक्टरों का कहना है कि लापरवाही करने पर हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर स्थिति हो सकती है, जो जानलेवा भी साबित हो सकती है.

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. लू लगने पर शरीर में पसीना आना बंद हो सकता है, त्वचा सूखी और लाल हो जाती है तथा सिरदर्द, कमजोरी, चक्कर और बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. विभाग ने सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें और यदि निकलना आवश्यक हो तो सिर को ढककर रखें. डॉक्टरों ने खानपान पर भी ध्यान देने की सलाह दी है. भारी, तेल-मसाले वाले भोजन से बचें और शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त पानी, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ओआरएस का सेवन करें. खाली पेट घर से बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है.

10 वीं में पूरक आने पर छात्रा ने कुएं में कूदकर दी जान

शहडोल. मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के गोहपारू थाना क्षेत्र के ग्राम बरई में दसवीं कक्षा की एक छात्रा ने परीक्षा में दो विषयों में पूरक आने पर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली. पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतका की पहचान टिंकल सिंह कंवर के रूप में हुई है.

परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद वह मानसिक रूप से व्यथित थी. आज सुबह उसका शव कुएं में तैरता हुआ मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया. मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है.

पटवारी ने जनसंपर्क अभियान का किया शुभारंभ

संगठन मजबूत करने के लिए कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित

विशेष संवाददाता

भोपाल, 17 अप्रैल. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को रवीन्द्र भवन में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया. सम्मेलन का उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाना और आमजन से सीधे संवाद की रणनीति को मजबूत करना रहा.

कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के आगमन के बाद वंदे मातरम् के गायन से हुई. इसके पश्चात महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया. अतिथियों का पारंपरिक सूत की मालाओं से स्वागत किया गया.

सम्मेलन में ब्लॉक स्तर के नेतृत्व की भूमिका, जिम्मेदारियों और संगठनात्मक महत्व पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया. डॉ. संजय कामले ने आगामी 'जनसंवाद सम्मेलनों' की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए संगठनात्मक गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने प्रदेशव्यापी ब्लॉक स्तरीय जनसंपर्क अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 25 वर्षों से प्रदेश में सत्ता से बाहर है, ऐसे में कार्यकर्ताओं को अधिक मेहनत करनी होगी.

पटवारी ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य व्यक्तिगत पद प्राप्ति नहीं, बल्कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करना है. उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश 'कर्ज, अपराध और भ्रष्टाचार' जैसी समस्याओं से जूझ रहा है. पार्टी ने घोषणा की कि 25 अप्रैल से 25 मई के बीच विधानसभा प्रभारी अपने क्षेत्रों का दौरा कर संगठनात्मक ढांचे का सत्यापन करेंगे, जिसके बाद जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे.

भोपाल में प्रदर्शन की घोषणा

संविदा श्रमिकों ने वेतन उल्लंघन का लगाया आरोप

विशेष संवाददाता

भोपाल, 17 अप्रैल. वैधानिक न्यूनतम वेतन न मिलने का आरोप लगाते हुए मध्यप्रदेश के हजारों अस्थायी, आउटसोर्स एवं संविदा श्रमिकों ने 28 अप्रैल को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की घोषणा की है.

श्रमिकों का कहना है कि सरकार द्वारा मासिक न्यूनतम वेतन 12,425 से 16,769 रुपये तय होने के बावजूद कई विभागों और औद्योगिक इकाइयों में उन्हें मात्र 3,000 से 5,000 रुपये तक ही भुगतान किया जा रहा है. इस अंतर के कारण स्कूलों, पंचायत सेवाओं, स्वास्थ्य संस्थानों और औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है. मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को भेजे गए पत्र के अनुसार इस प्रदर्शन को सांकेतिक सामूहिक आत्मदाह आंदोलन नाम दिया गया है.

जिला स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही हैं, जिसमें चौकीदार, पंप ऑपरेटर, सफाईकर्मी और अंशकालिक स्कूल कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हो सकते हैं.

केंद्र की मंशा पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

आरक्षण कानून : स्पष्टता-निरंतरता के अभाव का लगाया आरोप

विशेष संवाददाता

भोपाल, 17 अप्रैल. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को महिलाओं के आरक्षण कानून के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाते हुए उसके रुख में स्पष्टता और निरंतरता के अभाव का आरोप लगाया.

राजधानी भोपाल स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर सरकार की स्थिति पर प्रश्नचिह्न लगाया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में पारित इस कानून में स्पष्ट प्रावधान था कि इसके क्रियान्वयन से पहले जनगणना और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. नायक ने आरोप लगाया कि हालिया घटनाक्रम यह संकेत देते हैं कि केंद्र सरकार अपने ही प्रावधानों से पीछे हटती नजर आ रही है, जिससे देशभर में भ्रम की स्थिति बन रही है.

अभय दुबे ने भी जताई आपत्ति

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि पूर्व में अधिसूचना जारी होने के बावजूद इसी विषय से जुड़े संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश कर उस पर चर्चा और मतदान का औचित्य क्या है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पैनलिस्ट अभय दुबे ने भी बिना पूर्ण कानूनी अधिसूचना के संशोधन लाने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताते हुए केंद्र पर जातिगत जनगणना से बचने का आरोप लगाया.

साक्ष्य सुदृढ़ करने कार्यशाला आयोजित

विशेष संवाददाता

भोपाल, 17 अप्रैल. पुलिस मुख्यालय स्थित राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा 15 एवं 16 अप्रैल 2026 को दो दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य जिला एवं विशेष पुलिस इकाइयों में आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम प्रणाली और मापन संग्रहण इकाइयों के प्रभावी संचालन को सुदृढ़ करना था.

कार्यशाला का आयोजन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, जयदीप प्रसाद के निर्देशन में किया गया. इसका मुख्य फोकस आधुनिक तकनीकों के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य के संग्रहण और प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना रहा. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से आए विशेषज्ञों ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम सिस्टम और मापन संग्रहण इकाइयाँ के संचालन पर विस्तृत सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया. प्रतिभागियों को उन्नत तकनीकों के उपयोग, डेटा संग्रहण की शुद्धता तथा डिजिटल साक्ष्यों के सुरक्षित संरक्षण के संबंध में प्रशिक्षित किया गया.

आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 के तहत पुलिस एवं जांच एजेंसियों को आरोपियों, गिरफ्तार व्यक्तियों या दोषियों के फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक डेटा सहित विभिन्न माप एकत्र, सुरक्षित और विश्लेषित करने का अधिकार प्राप्त है.

खुले चेंबर में गिरने से मजदूर की मौत

ग्वालियर. शहर में सीवर चेंबर एक युवक की मौत का कारण बन गया. खुले पड़े सीवर चेंबर में गिरने से युवक की मौत हो गई. घटना गणेश कॉलोनी ओफो की बगिया की है. शुक्रवार की शाम स्थानीय लोगों ने युवक को चेंबर से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक अपनी मां से खाना बनाने की कहकर निकला था और उसके बाद वापस नहीं लौटा. हादसे का पता चलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गणेश कालोनी में रहने वाले सौरभ बाथम की सीवर के चेंबर में गिरने से मौत हो गई. सौरभ के बारे में बताया गया है कि वह मजदूरी करता था और शराब पीने का आदी था.

अवैध वेंडिंग के खिलाफ लगातार सघन अभियान

कार्रवाई का उद्देश्य : यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करना

भोपाल, 17 अप्रैल. रेल सुरक्षा बल द्वारा पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में यात्री गाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर अवैध वेंडिंग के खिलाफ लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है. इस कार्रवाई का उद्देश्य अनाधिकृत रूप से खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचने वालों पर रोक लगाना और यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करना है.

आरपीएफ द्वारा ट्रेनों में चल रही साइड पेंट्रीकार और पेंट्रीकार की आड़ में होने वाली अवैध वेंडिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और आउटर क्षेत्रों में भी बल की तैनाती की गई है. साथ ही, ट्रेनों में अनुरक्षण दल की भी तैनाती की गई है, जिससे निगरानी और अधिक प्रभावी हो सके.

रेल अधिनियम की धारा 144 के तहत की गई कार्रवाई में वर्ष 2024 में 7,267 प्रकरण दर्ज कर लगभग 98.50 लाख का अर्थदंड वसूला गया. वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 9,995 प्रकरणों तक पहुंची और 1.37 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला गया. वर्ष 2026 में 16 अप्रैल तक 2,433 प्रकरण दर्ज कर लगभग 29.09 लाख की वसूली की गई.

चंडीगढ़-मदुरई ट्रेन में अतिरिक्त कोच की सुविधा

भोपाल. रेलवे द्वारा समर सीजन में बढ़ती यात्री संख्या को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. इसी क्रम में भोपाल होकर संचालित चंडीगढ़-मदुरई एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त स्लीपर कोच अस्थायी रूप से जोड़ा जा रहा है. गाड़ी संख्या 20494 / 20493 चंडीगढ़-मदुरई-चंडीगढ़ एक्सप्रेस में यह अतिरिक्त स्लीपर कोच चंडीगढ़ से 20 अप्रैल 2026 को तथा मदुरई से 22 अप्रैल 2026 को लगाया जाएगा. इस निर्णय से यात्रियों को यात्रा के दौरान अधिक सीट उपलब्ध होंगी, जिससे वेटिंग लिस्ट में कमी आएगी और सफर अधिक आरामदायक बन सकेगा. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस अतिरिक्त कोच से न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, बल्कि भीड़ प्रबंधन में भी मदद मिलेगी. गर्मी के मौसम में ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस तरह के अस्थायी प्रबंध किए जाते हैं. यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं.

उपलब्धि | संकल्प से समाधान अभियान के तहत ढाई माह में मिले 47 .69 आवेदन

47 .68 लाख आवेदनों का किया निराकरण

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 17 अप्रैल. प्रदेश में चलाए गए संकल्प से समाधान अभियान की कुल अवधि 12 जनवरी से 31 मार्च के दौरान राज्य स्तर पर कुल 47.69 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 47.68 लाख प्रकरणों का समाधान करते हुए 99.9 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण किया गया.

इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संकल्प से समाधान अभियान से प्रदेश में नागरिकों की शिकायतों और आवेदनों का त्वरित, प्रभावी और पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित किया गया है. यह अभियान सुशासन को सुदृढ़ करने और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ है. अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम एवं वार्ड स्तर पर टीमों का गठन कर घर-घर जाकर आवेदन संग्रह किए गए और शिविर लगाकर आवेदनों का त्वरित समाधान किया गया. साथ ही पोर्टल आधारित एंट्री और ट्रैकिंग की गयी. निराकरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीएम हेल्पलाइन पर विशेष डैशबोर्ड के माध्यम से सतत मॉनिटरिंग भी की गई.

चार चरणों में संचालित हुआ अभियान

अभियान को चरणबद्ध रूप से प्रदेश में लागू किया गया. प्रथम चरण में 12 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक ग्राम एवं वार्ड स्तर पर आवेदन संग्रहण किया गया. द्वितीय चरण में 16 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन कर प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया. तृतीय चरण में 16 मार्च से 26 मार्च 2026 तक ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित कर शेष एवं नवीन आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित किया गया. चतुर्थ एवं अंतिम चरण में 26 मार्च से 31 मार्च 2026 तक जिला स्तर पर शिविर आयोजित कर सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया. अभियान में कुल 3 हजार 659 शिविर आयोजित किए गए. वहीं नल जल योजना के अंतर्गत नए नल कनेक्शन के लिए प्राप्त 1.39 लाख से अधिक आवेदनों में से 1.33 लाख से अधिक का निराकरण कर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा सुदृढ़ की गई.

सेवा वितरण को मिली नई गति

चालू खसरा एवं खतौनी की प्रतिलिपि के लिए सर्वाधिक 8 .71 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 8 .69 लाख से अधिक का सफल निराकरण किया गया. आयुष्मान भारत योजना में 5 .77 लाख से अधिक प्राप्त आवेदनों में से 5 .62 लाख से अधिक का निराकरण किया गया. चालू नक्शा प्रतिलिपि के लिए प्राप्त 4 .09 लाख से अधिक आवेदनों में से 4 .08 लाख से अधिक का निराकरण सुनिश्चित किया गया. ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण अनुज्ञा के लिए प्राप्त 3 .64 लाख से अधिक आवेदनों में से 3 .59 लाख से अधिक का निराकरण किया गया.

निर्माण श्रमिकों के पंजीयन से संबंधित 2 .31 लाख से अधिक आवेदनों में से 2 .18 लाख से अधिक का निराकरण किया गया. नो-ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त 1 .88 लाख से अधिक आवेदनों में से 1 .87 लाख से अधिक का निराकरण किया गया. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 1 .63 लाख से अधिक आवेदनों में से 1 .52 लाख से अधिक का निराकरण सुनिश्चित किया गया. किसान क्रेडिट कार्ड के प्राप्त 1 .50 लाख से अधिक आवेदनों में से 1 .48 लाख से अधिक का निराकरण किया गया. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राप्त 1 .44 लाख से अधिक आवेदनों में से लगभग सभी का निराकरण किया गया.

पेज एक का शेष

महिला आरक्षण बिल गिरा

बिल पर 56 महिला सांसदों और 130 सदस्यों ने अपनी बात रखी. 127 सीटों पर 20 लाख से ज्यादा आबादी है. 1972 में परिसीमन 525 से बढ़ाकर 585 हुई थी. महिला आरक्षण देना है तो परिसीमन जरूरी है. कांग्रेस ने गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की है. विपक्ष भ्रांतियां फैलाना चाहती है. पांच राज्यों में 129 से बढ़कर 195 सीटें होंगी. आरक्षण में रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है. 51 और 71 में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का विरोध किया था. कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया और आज तक संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है. कांग्रेस ने कभी ओबीसी से मंत्री नहीं बनाया. भाजपा ने ओबीसी से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर इतिहास रचा. मोदी सरकार में 27 मंत्री ओबीसी से है. विपक्ष ने महिला आरक्षण का भी विरोध किया. जबकि हमने 52 करोड़ महिलाओं को स्टार्टअप से जोड़ा है. 5 लाख करोड़ का बजट महिलाओं के लिए लाया गया. बिल का विरोध करने वाली कांग्रेस के भागने का मौका भी नहीं मिलेगा. विपक्ष ने मोदी के हर काम का विरोध किया, जबकि हर घर हर नल से महिलाओं को फायदा हुआ. शाह ने कहा- मैं टीवी पर विपक्ष के नेता का भाषण सुन रहा था. आपकी जिम्मेदारी है कि सदन की गरिमा बनी रही. वे कहते हैं कायर हैं, सरेंडर कर रहे हैं. असंसदीय शब्दों की भरमार लग जाती है. संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं.